खबर कोना

सरकार ने मसूर दाल के आयात पर 10 फीसद का शुल्क लगाया

नई दिल्ली, 9 मार्च (भाषा) ।

सरकार ने मसूर दाल पर 10 फीसद आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात को तीन महीने यानी इस साल 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के जरिये सरकार ने आठ मार्च से दालों पर पांच फीसद मूल सीमा शुल्क और पांच फीसद कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगाया है।अभी तक दालों के आयात को शुल्क-मुक्त रखा गया था।

कोझिकोड में रविवार को सड़क किनारे नारियल बेचता मजदूर।

शीर्ष सात का बाजार पूंजीकरण 2.10 लाख करोड़ रुपए बढ़ा

नई दिल्ली, 9 मार्च (भाषा)।

सूचकांक की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह सामूहिक रूप से 2,10,254.96 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) रहीं। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 1,134.48 अंक या 1.55 फीसद चढ़ा, वहीं एनएसई निफ्टी 427.8 अंक या 1.93 फीसद के लाभ में रहा।

टंकी साफ करने के दौरान चार मजदूरों की मौत

मुंबई, 9 मार्च (भाषा)।

दक्षिण मुंबई में एक निर्माणाधीन इमारत में पानी की टंकी साफ करते समय रविवार को चार मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। अधिकारियों ने इससे पहले मृतकों की संख्या पांच बताई थी। नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान हसीपाल शेख (19), राजा शेख (20), जियाउल्ला शेख (36) और इमांदु शेख (38) के रूप में की गई है, जबकि पांचवें व्यक्ति पुरहान शेख (31) का इलाज जारी है।

कमजोर आय और वैश्विक स्तर पर तनाव का असर

विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से निकाले 24,753 करोड़ रुपए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 मार्च।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों से 24,753 करोड़ रुपए (2.8 अरब डालर) निकाले हैं। कंपनियों की कमजोर आय और वैश्विक स्तर पर व्यापार तनाव बढ़ने के बीच एफपीआइ लगातार शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं। इससे पहले फरवरी में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 34,574 करोड़ रुपए और जनवरी में 78,027 करोड़ रुपए निकाले थे।

डिपाजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में अबतक एफपीआइ कुल 1.37 लाख करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, एफपीआइ ने इस महीने सात मार्च तक 24,753 करोड़ रुपए के शेयर बेचे है। यह उनकी शुद्ध निकासी का लगातार 13वां सप्ताह है। 13 दिसंबर, 2024 से एफपीआइ 17.1 अरब अमेरिकी डालर के शेयर बेच चुके हैं।

विदेशी निवेशकों द्वारा निरंतर बिक्री मुख्य रूप से वैश्विक और घरेलू कारकों के संयोजन के कारण है। मार्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका द्वारा मेक्सिको, कनाडा और चीन जैसे देशों पर ऊंचा शुल्क लगाए जाने तथा भारत सहित कई देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा से बाजार धारणा प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर कंपनियों के कमजोर नतीजों ने नकारात्मक धारणा को और बढ़ा दिया है। इससे एफपीआइ भारतीय शेयरों को लेकर सावधानी बरत रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह अनिश्चितता कमजोर रुपए से और बढ़ गई है, जिससे भारतीय परिसंपत्तियों का आकर्षण कम हो गया है। डेजर्व के सह-संस्थापक वैभव पोरवाल ने कहा कि रुपए में गिरावट ने एफपीआइ के लिए रिटर्न को कम कर दिया है। वहीं भारत की कर संरचना भी एक कारण है, जिसमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 फीसद कर और अल्पकालिक लाभ पर 20 फीसद कर है, जो वैकल्पिक बाजारों के विपरीत है, जो कम या शून्य कर वातावरण प्रदान करते हैं।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने चीन के शेयरों के प्रति बढ़ते आकर्षण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आकर्षक मूल्यांकन और चीन सरकार की बड़ी कंपनियों के लिए हालिया सकारात्मक पहल से एफपीआइ वहां का रुख कर रहे हैं। इसने चीनी शेयरों में उल्लेखनीय तेजी में योगदान दिया है।

हैंग सेंग सूचकांक ने सालाना आधार पर भारत के निफ्टी के नकारात्मक पांच फीसद रिटर्न की तुलना में 23.48 फीसद का रिटर्न दिया है। हालांकि, उन्होंने चेताते हुए कहा कि यह एक अल्पकालिक चक्रीय कारोबार हो सकता है, क्योंकि चीन के कॉरपोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन 2008 से लगातार उम्मीद से कम रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि में एफपीआइ ने बांड में सामान्य सीमा के तहत 2,405 करोड़ रुपए का निवेश किया और स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग से 377 करोड़ रुपए निकाले हैं। एफपीआइ का 2024 में भारतीय बाजार में निवेश काफी कम होकर 427 करोड़ रुपए रहा था। इससे पहले 2023 में उन्होंने भारतीय बाजार में 1.71 लाख करोड़ रुपए डाले थे, जबकि 2022 में वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि के बीच 1.21 लाख करोड़ रुपए की निकासी की थी।

इससे पहले फरवरी में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 34,574 करोड़ रुपए और जनवरी में 78,027 करोड़ रुपए निकाले थे। *डिपाजिटरी* के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में अबतक एफपीआइ कुल 1.37 लाख करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं।

'जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा से बाजार धारणा प्रभावित हुई'

मार्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका द्वारा मेक्सिको, कनाडा और चीन जैसे देशों पर ऊंचा शुल्क लगाए जाने तथा भारत सहित कई देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा से बाजार धारणा प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर कंपनियों के कमजोर नतीजों ने नकारात्मक धारणा को और बढ़ा दिया है। इससे एफपीआइ भारतीय शेयरों को लेकर सावधानी बरत रहे हैं।

अमेरिकी शुल्क

भारतीय दवा कंपनियों पर गहराएगा संकट, वाहन क्षेत्र पर असर कम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 मार्च।

अमेरिका में फार्मा आयात पर बढ़ाए गए शुल्क से भारतीय दवा निर्माताओं पर गंभीर असर पड़ सकता है क्योंकि इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे अन्य देशों के उत्पादों के मुकाबले निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। कम मार्जिन पर काम करने वाली छोटी दवा कंपनियों पर गंभीर दबाव पड़ सकता है, जिससे उन्हें एकीकरण या कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

दूसरी ओर, वाहन क्षेत्र पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका एक छोटा निर्यात बाजार है। भारत को बहुत अधिक शुल्क वाला देश बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क दो अप्रैल से लागू होंगे। भारत वर्तमान में अमेरिकी दवाओं पर लगभग 10 फीसद आयात शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय दवाओं पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाता है।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के साझेदार अरविंद शर्मा ने कहा कि हाल के इतिहास में, अमेरिका अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दवा उत्पादों का शुद्ध आयातक रहा है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका, भारत से दवा आयात पर भारी शुल्क लगाने का फैसला करता है, तो इसका असर भारतीय दवा क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और साथ ही इसकी घरेलू खपत भी बाधित होगी।

अमेरिका में दवा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा भारतीय दवा कंपनियां करती हैं। साल 2022 में अमेरिका में चिकित्सकों द्वारा लिखे गए पर्चों में 40 फीसद यानी 10 में से चार के लिए दवाओं की आपूर्ति भारतीय कंपनियों ने की थी। उद्योग सूत्रों के अनुसार, कुल मिलाकर, भारतीय कंपनियों की दवाओं से 2022 में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को 219 अरब डालर की बचत हुई और 2013 से 2022 के बीच कुल 1,300 अरब डालर की बचत हुई।

भारतीय कंपनियों की जेनेरिक दवाओं से अगले पांच वर्षों में 1,300 अरब डालर की अतिरिक्त बचत होने की उम्मीद है। शर्मा ने कहा कि भारत का दवा उद्योग वर्तमान में अमेरिकी बाजार पर काफी हद तक निर्भर है, और इसके कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग एक-तिहाई है। शर्मा ने कहा कि शुल्क लगाने से अमेरिका अनजाने में अपने घरेलू स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा और बदले में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच दुर्लभ हो जाएगी।

वाहन क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताते हुए इंडसला के साझेदार शशि मैथ्यूज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की हालिया घोषणाओं का विशेष रूप से भारतीय वाहन क्षेत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि भारत में प्रवेश भले ही अच्छी तरह से संरक्षित हो और इस प्रकार भारी कर लगाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में आयात के लिए जवाबी शुल्क, जो कि भारतीय मोटर वाहन क्षेत्र के लिए एक छोटा निर्यात बाजार है, हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा।

उत्पादन लागत बढ़ जाएगी

भारतीय दवा निर्माताओं पर गंभीर असर पड़ सकता है क्योंकि इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। *कम* मुनाफे पर काम करने वाली छोटी दवा कंपनियों पर गंभीर दबाव पड़ सकता है, जिससे उन्हें एकीकरण या कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

तीन सप्ताह में कोई बड़ी कंपनी नहीं हुई सूचीबद्ध

आइपीओ को लेकर छाई सुस्ती

नई दिल्ली, 9 मार्च (भाषा)।

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के लिए 2024 का साल काफी अच्छा रहा था, लेकिन अब इसमें सुस्ती आती दिख रही है। शेयर बाजारों में गिरावट के बीच पिछले तीन सप्ताह से किसी कंपनी का आइपीओ नहीं आया है। आइपीओ गतिविधियों में यह नरमी आंकड़ों में दिखती है।

जनवरी में केवल पांच कंपनियां और फरवरी में चार कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं, जबकि पिछले साल दिसंबर में 16 कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थीं। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड का आइपीओ हाल ही में आया था, जो 14 फरवरी को तीन दिन की बोली के लिए खुला था। हालांकि, धीमी गतिविधियों का रुझान स्पष्ट है, क्योंकि कम से कम तीन कंपनियों - एडवांस्ड सिस्टम-टेक, एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलाजीज और विनी कारपोरेशन ने जनवरी और फरवरी में अपने दस्तावेजों का मसौदा वापस लेकर अपनी आइपीओ की योजना वापस ले ली थी।

फरवरी में केवल चार कंपनियां सूचीबद्ध हुई हैं।

यह बदलाव 2024 के उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद आया है, जिसमें 91 सार्वजनिक निर्गम के जरिये सामूहिक रूप से 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। पिछले साल आइपीओ गतिविधियां मजबूत खुदरा भागीदारी, मजबूत अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ते निजी पूंजीगत व्यय से प्रेरित था।

इक्विरस के प्रबंध निदेशक और निवेश बैंकिंग के प्रमुख भावेश शाह ने एजंसी को बताया कि नरमी मुख्य रूप से द्वितीयक बाजार में, खासकर जनवरी और फरवरी में 'करेक्शन' के कारण है, जिसने कई सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर मूल्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

मुक्त व्यापार समझौते पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच 10वें दौर की वार्ता आज से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 मार्च।

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) सोमवार से ब्रसेल्स में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क लगाने की घोषणा से व्यापार युद्ध के व्यापक होने की आशंका के बीच यह बातचीत होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, ताकि इस साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यूरोपीय संघ के व्यापार व आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक की हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में प्रयास तेज करने पर चर्चा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत, चीन, कनाडा व मैक्सिको समेत अन्य देशों पर उच्च शुल्क लगाने की घोषणा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने पिछले महीने इस साल के अंत तक भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई थी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, भारत और यूरोपीय संघ 10-14 मार्च को ब्रुसेल्स में एफटीए के लिए दसवें दौर की वार्ता आयोजित करने वाले हैं। भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ ने जून, 2022 में आठ साल से अधिक समय बाद एफटीए पर वार्ता फिर से शुरू की थी। बाजारों को खोलने के स्तर पर मतभेदों के कारण बातचीत 2013 में रुक गई थी। दोनों पक्ष निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतक पर समझौते को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) का मानना है कि यूरोपीय संघ के कड़े पर्यावरण नियम, विशेष रूप से कार्बन कर, वनों की कटाई के नियम और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कानून भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए वार्ता में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हैं। वार्ता में इन मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जाएंगे।

बातचीत में कई अहम मुद्दों को हल करने की उम्मीद है, ताकि इस साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके।

ओला-उबर का जिक्र कर गृह मंत्री ने कहा

चालकों का बने राष्ट्रीय स्तर का संगठन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 मार्च।

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओला व उबर की तर्ज पर देश में चालकों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर चालकों की एक राष्ट्रीय सहकारिता टैक्सी प्रबंधन(कोओपरेटिव टैक्सी मेनेजमेंट) संस्था बनाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। वे गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित कर हे थे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त हमने भारत में कुल बीज उत्पादन का 25 फीसद हिस्सा कोआपरेटिव क्षेत्र से हो, ऐसा लक्ष्य भी केंद्र सरकार ने तय किया है। प्रधानमंत्री की अगुआई में भारत में सहकारिता क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है और इसमें अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक जैसी संस्थाओ को आगे बढ़कर बड़ा योगदान देना है। शाह ने कहा कि आजादी के बाद से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय बने और देश में सहकारिता अभियान को आज के समय के अनुकूल बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मांग को पूरा करते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और मंत्रालय ने आज तक 60 से अधिक पहल की हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने तय किया है कि 5 वर्ष में दो लाख कोओपरेटिव सोसायटी बनानी हैं और देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होंगी जहां प्राथमिक सहकारी समिति न हो। उन्होंने कहा कि हमने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के लिए नए उप कानून बनाकर अनेक प्रकार की गतिविधियों को इनके साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद की 572 सहकारी समितियों में से हर एक समिति को हमारी तीन बहुद्देश्यीय राष्ट्रीय सहकारी समितियों का सदस्य बनना चाहिए और इस दिशा में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक को काम करना चाहिए।

कहा 2,14,000 ग्राम पंचायत आज भारत नेट के माध्यम से जुड़ी हैं।

कांग्रेस ने कहा

'जीएसटी 2.0' को पूरी तरह सरल बनाना समय की मांग, कम दंडात्मक हो

नई दिल्ली, 9 मार्च (ब्यूरो)।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने रविवार को कहा कि जीएसटी में कोई भी बदलाव महज दरों में कमी से कहीं अधिक व्यापक होना चाहिए और वस्तु एवं सेवा कर के अगले चरण (जीएसटी 2.0) को पूरी तरह सरल तथा कम दंडात्मक बनाना चाहिए।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा था कि जीएसटी दरों में और कमी की जाएगी। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में जीएसटी 2.0 के जरिये एक अच्छे और सरल कर की परिकल्पना की थी। उन्होंने एक बयान में कहा कि गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है - क्या वे इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाएंगे? रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जीएसटी दरों में जल्द ही कमी की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोहराती है कि जीएसटी में कोई भी बदलाव महज दर में कमी से कहीं अधिक व्यापक होना चाहिए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पापकार्न के लिए कर की तीन दरों वाली व्यवस्था में बुनियादी सुधार किए बिना सिर्फ कारमेल पापकार्न पर कर घटाना महज दिखावा है। पापकार्न में चीनी मिलाने से इसे कारमेल पापकार्न कहते हैं और इस पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगता है। रमेश ने कहा कि समय की मांग है कि जीएसटी 2.0 को पूरी तरह सरल और कम दंडात्मक बनाया जाए।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 **शाखा कार्यालयः** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005

ई नीलामी सूचना

वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) "जैसा है जहां है आधार" और "जैसा है वैसा है आधार" पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर के आधार पर आयोजित की जाएगी।

क्रं. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	06.03.2025 तक वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	भारतीय रुपये में आरक्षित मूल्य	भारतीय रुपये में बयाना राशि जमा (ईएमडी)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	32069410000037 और 32069630000047	1) श्री कृष्ण, पुत्र. माईचंद (आवेदक), 2) श्री दीपक, पुत्र. कृष्ण (सह-आवेदक), 3) श्रीमती रोशनी, पत्नी कृष्ण (सह-आवेदक), 4) श्री देसराज, पुत्र. कृष्ण (सह-आवेदक)	24-04-2024	08.11.2024	रु.17,43,428/- (रुपए सत्रह लाख तैंतालीस हजार चार सौ अट्ठाईस मात्र)	01.04.2025 प्रातः 09:30 बजे को 05:00 शाम	रु. 34,07,000/- (रुपये चौंतीस लाख सात हजार मात्र)	रु. 3,40,700/- (रुपये तीन लाख चालीस हजार सात सौ मात्र)	15.04.2025 / 11:00 बजे दिन	11.04.2025 सायं 05:00 बजे से पहले। **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005

सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः प्लॉट/दुकान 121 वर्ग गज यानि 4 मरला तफसील - (1)2 मरले यानि 60.5 वर्ग गज भाग 1/38 कुल संपत्ति जराई 3 कनाल 16 मरले खेवट नंबर 113, खाता नंबर 131, रेक्ट और किला नंबर 17//17/1=3-16(2) 2, मरले यानि 60.5 वर्ग गज भाग 1/38 कुल संपत्ति जराई 3 कनाल 16 मरले खेवट नंबर 114 खाता नंबर 132 मुस्तिल और किला नंबर 17//17/2=3-16 गांव पलरी खुर्द तहसील राई जिला सोनीपत में स्थित वर्ष जमाबंदी 2017-2018 के लिए। श्री कृष्ण, पुत्र माईचंद के स्वामित्व में। **सीमाः** पूर्वः सुरेश का प्लॉट, पश्चिमः सत लाल का प्लॉट, उत्तरः बागपत रोड, दक्षिणः रोशनी का प्लॉट।

संपत्तियों को "जैसा है जहां है के आधार पर" और जैसा है जो है के आधार पर" आयोजित किया जा रहा है और ई-नीलामी "ऑन लाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल **https://bankauctions.in** और **www.foreclosureindia.com** पर आयोजित की जायेगी या अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4 क्लोजर , श्री उत्कर्ष आदेश, संपर्क नंबरः 9515160064 . ईमेल आईडीः **info@bankauctions.in / adesh@bankauctions.in.** से संपर्क कर सकते हैं।

ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकृत अधिकारी श्री शशि कुमार (मोबाइल नं. 8700277112), श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463), एवं रंजन नायक (मो. 6362951653), से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है।हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को अद्यतन तिथि के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता हैनीलामी की तारीख से पहले ब्याज और सहायक खर्च, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 10.03.2025 , स्थानः सोनीपत **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

निवेश के लिहाज से चांदी की चमक बरकरार, 11 फीसद का दिया मुनाफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 मार्च।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच चांदी भी निवेशकों को निवेश के लिहाज से आकर्षित कर रही है और इसने इस साल अबतक लगभग 11 फीसद का रिटर्न (प्रतिफल) दिया है।

इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत बुनियाद और अन्य मूल्यवान धातुओं की तुलना में सस्ती कीमतों के साथ, चांदी का प्रदर्शन रिटर्न के लिहाज से अगले दो-तीन साल बेहतर रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सोने की तुलना में चांदी में उतार-चढ़ाव अधिक होता है। इसका कारण यह निवेश परिसंपत्ति के साथ-साथ औद्योगिक धातु के रूप में उपयोगी और आकर्षक है। लेकिन यह सोने की तुलना में अधिक किफायती है, जिससे छोटे निवेशकों के लिए इसे खरीदना आसान हो जाता है। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष (जिंस) राहुल कलंत्री ने कहा कि देश में चांदी की कीमत एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) वायदा में बीते वर्ष 17.50 फीसद चढ़ी है और यह 10 साल के औसत रिटर्न 9.56 फीसद से अधिक है। पिछले दो साल में इसमें मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है और इस साल भी अबतक इसमें 11 फीसद की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि चांदी के हाल के प्रदर्शन को देखते हुए निवेशक आने वाले समय में इसमें संभावनाओं को लेकर सतर्क हुए हैं। वर्तमान में, चांदी वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 25 अप्रैल, 2011 को निर्धारित अपने रिकार्ड 50 डॉलर प्रति औंस से लगभग 35 फीसद नीचे कारोबार कर रही है। कीमत का यह स्तर बाजार में तेजी की उम्मीद करने वालों के लिए निवेश को लेकर एक आकर्षक प्रवेश बिंदु का संकेत हो सकता है।

www.readwhere.com